

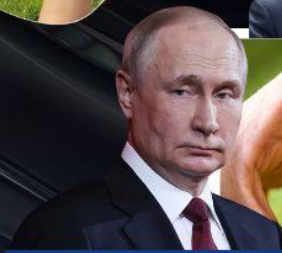
**BREAKING
NEWS**



CURRENT AFFAIRS

UPSC-CSE

05 SEPTEMBER 2024



Abhay Sir /

Topic 1 :- NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता



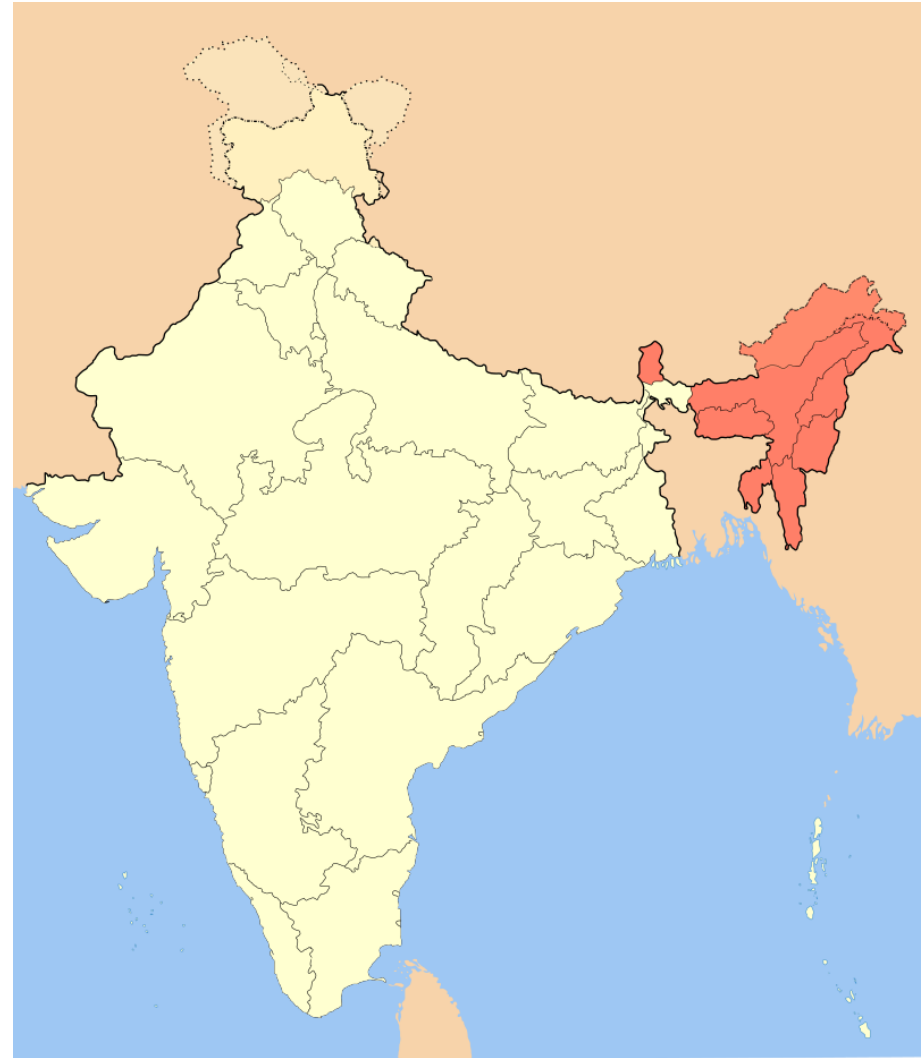
चर्चा में क्यों :-

- हाल ही में केंद्र सरकार और त्रिपुरा राज्य सरकार ने दो उग्रवादी संगठन NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता किया।



समझौता क्यों :-

- पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा समाप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए



किन किन के मध्य :-

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और NLFT और ATTF के मध्य
- यह समझौता पूर्वोत्तर के लिए 12वां और त्रिपुरा से संबंधित तीसरा समझौता है।



पूर्वोत्तर को विकास पैकेज :-

- 2500 करोड़ रुपये के विकास पैकेज की पूर्वोत्तर के लिए घोषणा।



क्या है NLFT और ATTF :-

NLFT और ATTF के गठन का उद्देश्य:-

- पूर्वोत्तर राज्य के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर हथियार के बल पर त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना ।



NLFT और ATTF के कार्य :-

- 1. हिंसक गतिविधियों में शामिल होना ।
- 2. लोगों के बीच आतंक और हिंसा फैलाना ।



Topic 2 :- दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि



चर्चा में क्यों :-

- राष्ट्रपति ने हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि की है: बोर्ड-पैनल बनाने के साथ नियुक्ति भी कर सकेंगे; पहले दिल्ली सरकार के पास अधिकार था



क्या वृद्धि हुई :-

- ❑ LG दिल्ली में अब अथॉरिटी बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे।
- ❑ साथ ही वे इन सभी निकाय में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे।
- ❑ पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास था।
- ❑ उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि का यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है।



क्या क्या बदलाव हुए :-

- ❑ उपराज्यपाल अब MCD में पार्षद नियुक्त सीधे कर सकते हैं
- ❑ पहले उन्हें इस कार्य के लिए दिल्ली सरकार से सलाह लेना जरूरी था।
- ❑ सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को आदेश दिया था की दिल्ली नगर निगम में 10 मेंबर नॉमिनेट करने के उपराज्यपाल (LG) के फैसले को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है।



एल्डरमैन की नियुक्ति :-

- इनकी नियुक्ति एलजी द्वारा की जाती है दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अनुसार, 25 वर्ष से अधिक आयु के 10 लोगों को दिल्ली नगर निगम के लिए एल्डरमैन नियुक्त ।



एल्डरमैन बनने के लिए योग्यता:-

- ❑ नगरपालिका से जुड़े काम का अनुभव और नॉलेज होना जरूरी ।
- ❑ राष्ट्रपति ने दो महीने पहले भी जम्मू-कश्मीर के LG की शक्तियों में वृद्धि की थी



- ❑ केंद्र सरकार द्वारा 13 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) की प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि की थी।
- ❑ जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार LG की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी।
- ❑ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के द्वारा LG को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई हैं।
- ❑ उपराज्यपाल अब जम्मू-कश्मीर में पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस (AIS) से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे।



AIS

दिल्ली के उपराज्यपाल :-

- विनय कुमार सक्सेना हैं
- इनकी नियुक्ति 26 मई 2022 को 22वें उपराज्यपाल के रूप में की गई थी।



Topic 3 :- 23वें विधि आयोग का गठन



- ❑ राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी

23वें विधि आयोग का कार्यकाल :-

- ❑ 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक के लिए (तीन साल) ।
- ❑ **सदस्य :-** अध्यक्ष, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन एवं अंशकालिक सदस्य ।



कार्य:

- ❑ 1. भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुधारों की समीक्षा करना और सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।
- ❑ 2. ऐसे कानून को अप्रचलित है या जो प्रयोग में नहीं है उनकी समीक्षा करना।
- ❑ 3. कानूनों को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए उनकी समीक्षा करना तथा आवश्यक संशोधन के लिए सुझाव देना।
- ❑ 4. वर्तमान में प्रचलित कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करना , तथा जटिल कानूनों को सरलीकृत करना।



- ❑ 5. कानून को इतना सरल और सस्ता बनाना जिससे गरीबों को भी आसानी से न्याय प्राप्त हो सके।
- ❑ 6. न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना जिससे न्याय मिलने में होने वाली देरी को समाप्त किया जा सके ।
- ❑ 7. केंद्रीय कानूनों में संशोधन हेतु सुझाव देना जिससे विसंगतियों तथा असमानताओं को दूर किया जा सके ।



Topic 4 :- देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान



हाल ही में देश के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान की पहली सफल उड़ान का आयोजन किया गया।



नीति एवं योजनाएं:

- इसमें रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति; "मेक इन इंडिया"; "सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची" की अधिसूचना; रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (Innovations for Defence Excellence: iDEX); आदि शामिल हैं



साझेदारी और वैश्विक सहयोग:

- इसमें भारत के निजी क्षेत्रक और वैश्विक मूल उपकरण विनिर्माताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी मॉडल, रक्षा क्षेत्रक में FDI की सीमा को बढ़ाकर स्वचालित मार्ग से 74% और सरकारी मार्ग से 100% करना; आदि शामिल हैं।



अन्य:

- आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण, रक्षा औद्योगिक गलियारा, सृजन पोर्टल, आदि

